



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

Address: Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002  
Phone: 0751-2323968  
Fax: 0751-2432194

पता: लेखा भवन ज्वांसी रोड, ग्वालियर-474002  
दूरभाष: 0751-2323968  
फैक्स: 0751-2432194



क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./राजस्थान-3/2024-25 ~~12348~~ दिनांक:- 12-9-24

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी  
मध्यप्रदेश

विषय:-सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के प्री. 2016 के संशोधित प्रकरणों में ऐरियर के भुगतान, अतिरिक्त पेंशन के भुगतान, घरेलू सहायता भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, जयपुर से प्राप्त प्राधिकार क्रमांक पेंशन प्राधि./आदेश/के-107/2024-25/1420 दिनांक 13.08.2024.  
2. निदेशालय, पेंशन, जयपुर का पत्र क्रमांक पी.आ.1/न्यायिक/2023/31425-ए दिनांक 22.07.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, जयपुर से प्राप्त संदर्भित पत्र क्रमांक 1. के द्वारा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के प्री. 2016 के संशोधित प्रकरणों में ऐरियर के भुगतान, अतिरिक्त पेंशन के भुगतान, घरेलू सहायता भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय प्रधान महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट [www.agmp.nic.in](http://www.agmp.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

कृपया अपने स्तर पर भुगतान संबंधी कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./राजस्थान-3/2024-25 ~~12348~~ दिनांक:- 12-9-24

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन प्राधि., कार्यालय महालेखाकार राजस्थान, जयपुर से प्राप्त प्राधिकार क्रमांक पेंशन प्राधि./आदेश/के-107/2024-25/1420 दिनांक 13.08.2024 के संबंध में सूचनार्थ।

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

R-354 922 425

+47541145

क्रमांक:- पेंशन प्राधि./आदेश/के-107/2024-25/1420  
संख्या / No.....

89353



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date... 13/08/24

3005430

39

प्रधान महालेखाकार (A&E) II,  
मध्य प्रदेश, लेखा भवन,  
शांती रोड, जालिमर-474002

विषय:- सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के प्री. 2016 के संशोधित प्रकरणों में ऐरियर के भुगतान, अतिरिक्त पेंशन के भुगतान, घेरलू सहायता भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशालय, पेंशन, जयपुर का पत्रांक पी.आर.1/न्यायिक/2023/31425-ए दिनांक 22.07.2024 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक पी.आर.1/न्यायिक/2023/31425-ए दिनांक 22.07.2024 द्वारा आदेशों की प्रतियां पुनः प्राप्त हुई प्राप्त हुई है।

उक्त आदेश दिनांक 28.05.2024 को पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त आदेश पुनः प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः आप से निवेदन है कि आपके राज्य में स्थित सभी कोषालयों को उपरोक्त आदेशानुसार निर्देश प्रदान कर पावती इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करावें।

उक्त कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार  
(आदेश की कोपी)

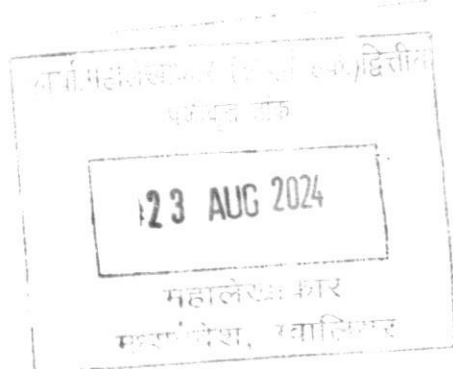
भवदीय

Sh. Madhav

23/8/24

U

U-43  
28-8-24



वरि.लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष : (0141)2385431-39, फ़ैक्स: (0141)2385263

Janpath. Jaipur-302005, Tel.: (0141)2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पेंशन एवंपेंशनर्सकल्याण,  
विद्युतमार्ग, ज्योतिनगर, जयपुर (राजस्थान) 302005  
ईमेल-dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687  
वेबसाईट :- pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक: पीआर.1 / न्यायिक / 2023  
महालेखाकार,  
कार्यालय महालेखाकार,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

31425-A  
22/7/24

विषय:- सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के प्री.2016 के संशोधित प्रकरणों में ऐरियर के भुगतान, अतिरिक्त पेंशन के भुगतान, घरेलू सहायता भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता के भुगतान के संबंध में  
संदर्भ:- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 12(4) एफडी/रूल्स/2023 दिनांक 13.07.2023, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक f.26(55)Nyay/2015part IV दिनांक 12.03. 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ12(4)एफडी/रूल्स/2023 दिनांक 13.07.2023 के अनुसरण में विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पूर्व निम्नांकित से.नि. न्यायाधीशों के पेंशन संशोधन कर संशोधित अधिकृतियां जारी कर आपको भिजवाई जा चुकी है:-

Auth.No.	Name	Treasury Name	Dis.Date
24045	Sh.Dinesh Chandra Hajeia	Mussoorie(Dehradun)	02/11/2023
36626	Sh. Kamta Prasad Mishra.	Pay and Accounts Officer No 5 Tees Hazari New Delhi	30/10/2023
152876	Sh.K.L.Chandok	Tees Hazari New Delhi	03/10/2023
176063	Sh.Ravi Kumar Mathur	Tees Hazari New Delhi	03/10/2023

माननीय उच्चतम न्यायालय ने संशोधित अधिकृति के अनुरूप संशोधित पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं एलटीए का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किए थे परन्तु आदिनांक तक भी कल्पित प्रकरणों में न्यायिक अधिकारियों के ऐरियर का भुगतान बकाया है।

इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों के कुछ प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत देय घरेलू सहायता भत्ता एवं मेडिकल भत्ते के ऐरियर की राशि का अभी तक भी भुगतान बकाया है।


कुछ प्रकरणों में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को 75 वर्ष पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि का भी भुगतान बकाया है।

अतः आप उपरोक्त कोषाधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए न्यायिक अधिकारियों के समस्त बकाया

पेंशन परिलाभ (ऐरियर), देय घरेलू सहायता भत्ता एवं मेडिकल भत्ते के ऐरियर की राशि का भुगतान अविलम्ब कराना सुनिश्चित करावें तथा की गयी कार्यवाही की वस्तुस्थिति से प्रकरणवार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना सुनिश्चित करें। इस क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.07.2024 की प्रति भी सुलभ संदर्भ हेतु सलग्न है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

  
(डॉ. देवराज)  
निदेशक

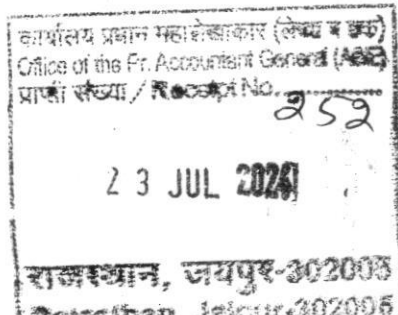
दिनांक

क्रमांक: पीआर.1 / न्यायिक / 2023

प्रतिलिपि निम्न कित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- Pay and Accounts Officer No.5 Tees Hazari New Delhi
- Pay and Accounts Officer/ Treasury Officer, Tees Hazari New Delhi
- Treasury Officer, Mussoorie (Dehradun)

निदेशक





**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

No. F.12(4)FD/Rules/2023

Jaipur, dated : 13 JUL 2023

ORDER

**Sub: Retirement benefits, revision of pension / family pension in respect of Judicial Officers.**

In supersession of Finance Department Order no. F. 12(4)FD/Rules/2010 dated 27.08.2010 as amended from time to time, the Governor is pleased to order that :-

**1. The retirement benefit to the judicial officers, who retire / retired on or after 01.01.2016 shall be allowed as under :**

- (a) The pension and family pension shall be @ 50% and 30% respectively of the last pay drawn at the time of retirement.
- (b) Age of Superannuation: The age of Superannuation of Judicial Officers shall be 60 years as at present.
- (c) Qualifying service for earning full pension shall be 20 years.
- (d) Last pay drawn shall continue to be taken as emoluments for purpose of calculation of pension.
- (e) Commutation of pension shall be 50% of the pension with restoration after 15 years.
- (f) The payment of DCRG and retirement Gratuity is revised to Rs.20 lacs w.e.f. 01.01.2016 as per Rule 50(1)(a) of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (for this purpose Finance Department has already given concurrence vide ID No. 592300031 dated 08.03.2023). The maximum limit for retirement gratuity/death gratuity shall be increased by 25% whenever DA rises by 50%.
- (g) Family Pension shall be paid to eligible family member(s) as per Rule 54 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

*blit*

The aforesaid provisions will come into force w.e.f. 01.01.2016 and will be applicable to judicial officers who have retired or ceased to be in service due to death or retirement on or after 01.01.2016.

**2. The pension / family pension of the judicial officers, who retired / died prior to 01.01.2016 shall be revised as under :**

(a) The revised pension / family pension of the judicial officers who have retired or died while in service prior to 01.01.2016 shall be as under:

(i) The existing pension / family pension shall be revised by the multiplier factor of 2.81

or

Retired / died Judicial Officers to be placed notionally at the corresponding stage of the fitment table (indicated in item (v)) in new proposed pay on the basis of last pay drawn at the time of retirement and the revised pension and family pension shall be @ 50% and 30% respectively of the new proposed pay as per fitment table, whichever is higher.

(ii) The quantum of family pension shall be worked out in the same manner as quantum of pension is worked out.

(iii) Income limit, in relation to dependent family members (other than the spouse) for being eligible to get family pension shall be not less than Rs.30,000/- per month (rupees thirty thousand per month).

(iv) The benefits of number of years of practice at bar subject to maximum of weightage of ten years will be given to direct recruits of Higher Judicial Services, who retired prior to 01.01.2016.



3. The Additional quantum of pension / family pension shall be admissible to the Judicial Officers on completion of age of and at the revised rates specified below w.e.f. 01.01.2016:

Age of Pensioner / Family Pensioner	Additional quantum of pension
From 75 years to less than 80 years	20% of revised basic pension/family pension
From 80 years to less than 85 years	30% of revised basic pension/family pension
From 85 years to less than 90 years	40% of revised basic pension/family pension
From 90 years to less than 95 years	60% of revised basic pension/family pension
From 95 years to less than 100 years	80% of revised basic pension/family pension
100 Years and above	100% of revised basic pension/ family pension

4. Arrears of pension / family pension to be paid after adjusting payment of interim relief already paid @30% of basic pension / family pension under Law and Legal Affairs Department Order no. F. 10(5)Law/2018 dated 21.05.2018

5. Payment as per revised rate of pension / family pension shall be made w.e.f. 01.07.2023 and arrear of pension / family pension for the period from 01.01.2016 to 30.06.2023 shall be made 25% by 31.08.2023 another 25% by 31.10.2023 and remaining 50% by 31.12.2023.

By order of the Governor,

  
(Rohit Gupta)

Secretary, Finance (Budget)

(v) Fitment table :-

S.No	Pay as per FNJPC	Existing Pay	New Proposed Pay
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12500	38610	111000
15	12800	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190
27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960
34	20050	61690	178150
35	50500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100

- (b) The aforesaid provisions will come into force w.e.f. 01.01.2016 and will be applicable to judicial officers who have retired or ceased to be in service due to death or retirement prior to 01.01.2016.

*bolit*



GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
**LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT**

No.F. 26(55) Nyav / 2015 part IV

Dated 12.03.2024

ORDER

Pursuant to the Judgement dated 04.01.2024, passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/2015, **All India Judges Association vs Union of India** on the recommendations of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) relating to the revision of pay, pension and allowances to the Judicial Officers, and pursuant to Cabinet Order No. 17/2024 dated 11.03.2024, the Governor of Rajasthan is pleased to issue following orders:-

**1. House Building Advance (HBA):-**

- (i) HBA shall be made available to judicial officers in terms of the House Building Advance Rules, 2017; and
- (ii) HBA shall be available to judicial officers also for the purchase of a ready built house from private individuals subject to such safeguards as may be prescribed by the State Government in consultation with Rajasthan High Court.

**2. Children Education Allowance (CEA):-**

The Children Education Allowance shall be available to the judicial officers at the following rates:-

- (a) Rs 2,250 per month as CEA and Rs 6,750 per month as hostel subsidy for two children up to Class 12;
- (b) For children with special needs, the reimbursement would be at double the rate stated in (a);
- (c) When the DA increases by 50%, the allowances and subsidy shall be increased by 25%;
- (d) The rights of officers who are already receiving this benefit will not be adversely affected by the recommendation; and
- (e) This allowance shall be available w.e.f. 01.04.2019.



**3. City Compensatory Allowance (CCA):-**

CCA shall be discontinued w.e.f. 1<sup>st</sup> March, 2024.

**4. Concurrent Charges Allowance:-**

In partial modification of order No. F.11(3)Nyay/2002, dated 08.09.2005 of this Department, the following order is made:-

1. The concurrent charge allowance shall be available maximum at the rate of 10% of the minimum of the scale of the additional post held beyond a period of ten working days.
2. No upward revision in the percentage of the Concurrent Charge allowance.
3. High Court shall decide the Concurrent Charge allowance to be available to the Officer within the ceiling of 10% on the basis of the number of days worked, the quantum of judicial work turned out and the administrative work handled.
4. The criterion laid down by FNJPC be dispensed with and there shall not be any insistence on the performance of 'appreciable judicial work' of the Court concerned.

**5. Dearness Allowance:-**

Dearness Allowance shall be paid at the rate fixed by the Central Government.

**6. Earned Leave Encashment -**

In continuation and partial modification of order No. F. 11(3) Nyay/2002, dated 08.08.2005 issued by this Department, the following order is made:-

1. No enhancement in the maximum limit of 300 days leave encashment at the time of retirement.
2. A judicial officer shall be entitled to encash:-



- (a) 10 days earned leave while availing LTC subject to maximum 60 days – 10 earned leave at a time up to six occasions during the entire service.

A judicial officer shall be entitled to encash 10 days earned leave for each LTC availed by him from the existing block year of 2015-2019 and onwards except the extended LTC availed after 01.01.2016.

- (b) 30 days in a block of two years.  
(c) S.No.(a) and (b) shall be in addition to the right of the Judicial Officers to encash up to 300 days EL at the time of retirement.

3. In case of officers who have retired and while granting leave encashment at the time of retirement, the leave encashment availed during service stand adjusted, shall be paid the amount of the so adjusted earned leave, at the time of retirement, within a period of three months from the date of acceptance of the report.

#### **7. Higher Qualification Allowance:-**

In partial modification of order No. F.11(3) Judl/2007, dated 07.05.2003 issued by this Department, the following order is made:-

1. The Judicial Officers shall be granted three advance increments for acquiring higher qualification i.e. post-graduation in law and one more advance increment if he acquires Doctorate in Law.
2. The advance increments once granted for post-graduation degree or Doctorate in law shall not be granted again if, in future, the officer acquires post graduate or Doctorate degree in any other subject.
3. The advance increments shall be available to the officer who had acquired the post-graduation degree or Doctorate either before recruitment or at any time subsequent thereto while in service.



4. The advance increments shall be granted from the date of initial recruitment, if the officer has already acquired the post-graduation degree or Doctorate and from the date of acquiring the post-graduation or Doctorate degree, if acquired after joining the service.
5. The advance increments shall be available to the officers if the higher qualification has been acquired through regular studies as well as distant learning programmes.
6. The advance increment shall be available when the Officer is promoted from Civil Judge to Senior Civil Judge and from Senior Civil Judge to District Judge cadre also at ACP stage.
7. The advance increments shall be available in the District Judge Cadre from District Judge (Entry Level) to District Judge (Selection Grade) and from District Judge (Selection Grade) to District Judge (Super Time Scale).
8. The advance increments for all practical purposes shall be part of salary and Dearness Allowance shall be available on the same.
9. The discontinued benefit of advance increments for higher educational qualification may be restored from 01.01.2016 in accordance with SNJPC recommendations and pay shall be revised accordingly without any notional benefit.

**8. Hill Area/ Tough Location Allowance:-**

1. Hill Area/Tough Location Allowance @Rs.5000/- per month shall be paid to the Judicial Officers posted in hill areas/tough locations.
2. Hill areas/Tough locations will be specified by the Rajasthan High Court.
3. This allowance shall be available w.e.f. 01.01.2016.

**9. Home Orderly/ Domestic Help Allowance:-**

1. The Home-cum-office orderly allowance shall be available to the serving Judicial officers at the following rates w.e.f. 01.01.2020 :-



- (i) District Judges : minimum wages of one unskilled worker in the State subject to minimum of Rs.10,000/- per month.
- (ii) Senior Civil Judges and Civil Judges : 60% of the minimum wages of one unskilled worker in the State subject to minimum of Rs.7,500/- per month
- (iii) The Home Orderly Allowance for serving Judicial Officers shall stand increased by 5% on yearly basis from 01.01.2020.

2. In continuation and partial modification of order No. F.26(12) Nyay/2009 dated 03.05.2010 issued by Department of Law and Legal Affairs, Rajasthan Government, Domestic Help Allowance to the pensioners and family pensioners shall be available at the following rates from 01.01.2016:-

- (a) (i) Pensioner : Rs 9,000/- per month.  
(ii) Family pensioners : Rs.7,500/- per month.
- (b) For pensioners and family pensioners this allowance shall stand increased by 30% on completion of five years from 01.01.2016 that is, w.e.f. 01.01.2021, i.e. Rs 11700 and Rs 9750 respectively from 01.01.2021.

#### 10. House Rent Allowance:-

##### HRA:-

In continuation and partial modification of order No. F.26(55) Judl/2015 dated 27.12.2022 issued by this Department, the following order is made:-

- (i) Judicial officers who are allotted official quarters for residence shall not be entitled to HRA;
- (ii) Judicial officers residing in their own houses, including the house of a parent or spouse, shall be entitled for the recommended HRA with effect from 01.01.2016 after obtaining permission from the High Court to reside in their own house and judicial officers already residing in hired accommodation will be entitled to the recommended HRA with effect from 01.01.2020, subject to the actual rent paid within the said ceiling;



- (iii) The Office of the Principal District Judge or equivalent shall pay rent directly to the landlord, in such case, the officer is not eligible to draw HRA; and
- (iv) The SNJPC rates of HRA should be applicable to all Judicial Officers as per the notification dated 07.07.2017 which was issued after the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission (CPC) by the Central Government:-

Classification Of Cities	Rates of HRA/PM as percent of basic pay
X	24%
Y	16%
Z	8%

However the minimum rates prescribed are 5400/-, 3600/- and 1800/- respectively and the rate will be changed in accordance with the change in Dearness Allowance in the following terms:-

Classification Of Cities	Rates of HRA/PM as percent of basic pay	When DA Crosses
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	9%	25%
	10%	50%

The High Court is at liberty to upgrade and add the cities in different classes.



### **Furniture & Air Conditioner Allowance:-**

In continuation and partial modification of order No. F.11(03)Nyay/2002 dated 10.11.2015 issued by this Department, the following order is made:-

1. Furniture grant of Rs.1.25 lakhs every five years shall be provided to the Judicial Officer subject to production of proof of purchase.
2. Household electrical appliances can also be purchased by availing of the said grant.
3. The Officers having not less than two years of service shall also be eligible for this allowance.
4. The option to purchase the furniture being used by the officer at the depreciated rate shall be available at the time of fresh grant or retirement.
5. Apart from the furniture grant, one air-conditioner shall be provided at the residence of every Judicial Officer once in every five years. Judicial Officer may purchase one Air Conditioner up to Rs. 75,000/ every five years (block 2016-2020, 2021-2025 and so on).
6. The five yearly block period regarding Furniture Grant and Air-Conditioner is re-determined as Calendar Year 2016-2020 and so on.
7. The condition of retaining the furniture at depreciated value has to be followed but this condition shall not apply for items already purchased under existing grant and consumable articles. Condition of retention at depreciated value shall be applied with prospective effect. The condition of retaining at depreciated value shall not apply to the Air-Conditioner.
8. Furniture grant is admitted on five yearly block period. The First block for Furniture Grant shall commence from 01.01.2016 up to 31.12.2020 (Calendar years) and so on.
9. Furniture Grant issued during the block of 2015-2019 will be adjusted against the first block of 2016-2020. If any judicial



officer has received the second grant thereafter, the same shall be adjusted against the second block of 2021-2025.

10. Arrears of Furniture Grant shall be admissible subject to the stipulation that Judicial Officers will submit the proof of utilisation and payment.
11. Any officer who had already purchased furniture and reimbursed according to existing provisions, shall be reimbursed the differential amount subject to following conditions:-
  - (i) he had already submitted the vouchers and receipts of purchase of furniture; and
  - (ii) the maximum amount to be reimbursed shall not exceed the limit of Rs. 1.25 lakhs or the actual amount paid, whichever is less.

**11. Leave Travel Concession (LTC)/ Home Travel Concession (HTC):-**

In continuation and partial modification of order No. F.26(12) Nyay/2009 dated 24.02.2011 issued by this Department, the following order is made:-

- (i) Encashment of 10 days earned leave while availing LTC (not HTC) (subject to the maximum of 60 days) shall be available. The same will be in addition to encashment of 300 days at the time of retirement and 30 days in a block of two years.
- (ii) (a) The Judicial Officers shall be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of 3 years.  
(b) As far as fresh recruits are concerned, the HTC shall be allowed 2 times in the first block of 3 years. However, the block of 3 years will commence on completion of the period prescribed for probation (not necessarily declared).
- (iii) (a) The Judicial officers, irrespective of their rank, shall be allowed to travel by air and the reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets have been purchased either directly from the Airlines or from the agents authorized, namely, Ashoka Travels, Balmer and Lawrie and IRCTC by the Central/State





Government subject to further addition or deletion of the authorized agent by the Central/State Government.

(b) The other details such as class of travel, advance etc. shall be governed by the respective Rules/Orders of the State.

- (iv) The Judicial officers shall be allowed to carry forward LTC anywhere in India beyond retirement for a period of one year.
- (v) The LTC/HTC facility shall not be available to the retired judicial officers.
- (vi) The Judicial officers shall not be required to avail of earned leave only for LTC/HTC purpose and they may be permitted to avail of casual leave as a prefix and suffix to the extent of two days.

Note:- Block Year for LTC/HTC will commence from 01/01/16 and blocks of year will be redetermined accordingly as 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024 and so on.

The block year 01/11/2015-31/10/2019 is redetermined as 01/01/16-31/12/2018 and similarly the block year 01/11/2019-31/10/2023 is redetermined as 01/01/2019-31/12/2021 and so on.

The present block period for LTC/HTC shall exist only up to 31.12.2024.

## **12. Medical Allowance/ Medical Facilities:-**

In compliance of the judgement of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/2015, *All India Judges Association vs Union of India* dated 04.01.24, the following order is made:-

- (i) Fixed medical allowance shall be payable at the rate of Rs.3,000/- per month to the serving Judicial Officers, with effect from 01.01.2016, instead of Rs 1000 as payable under Rule 8 of Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008;
- (ii) Fixed medical allowance shall be payable at the rate of Rs.4,000/- per month to the pensioners and family pensioners, with effect from 01.01.2016, instead of Rs 1500 as payable to



pensioners under Rule 8 of Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008;

- (iii) The spouse or other dependents of Judicial Officers drawing family pension shall also be eligible for medical facilities/ reimbursement at par with the pensioners of the judiciary; and
- (iv) Other substantive recommendations of SNJPC regarding Medical facilities and reimbursement of medical expenses are also accepted but detailed orders/consequential amendments in the said Rules of 2008 shall be issued/made subsequently.

### **13. Newspaper and Magazine Allowance :-**

In continuation and partial modification of order No. F.11(3) Nyay/02 part, dated 08.09.2005 issued by this Department, the following order is made:-

1. Reimbursement for newspaper and magazines shall be Rs.1000/- per month for District Judges (two newspapers and two magazines) and Rs.700/- per month for Senior Civil Judges and Civil Judges (two newspapers and one magazine).
2. The reimbursement shall be on half yearly basis from January to June and July to December, on the basis of self certification.
3. The allowance at the above mentioned rates shall be available from 01.01.2020.

### **14. Robe Allowance:-**

In continuation and partial modification of order No. F.26(12) Nyay/2009 part, dated 24.02.2011 issued by this Department, the following order is made:-

- (i) An allowance of Rs. 12,000 will be payable once in three years with effect from 01.01.2016; and
- (ii) The block period for Robe Allowance is re-determined as Calendar year 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024 and so on.

### **15. Special Pay for Administrative Work:-**

1. Special Pay for Judicial officers doing administrative work shall be payable to all the judicial officers at the following rate:



- (a) Principal District and Sessions Judges (Present/Previous):  
Rs.7000/- per month;
  - (b) Other District Judges including I Additional District  
Judges: Rs. 3500/- per month;
  - (c) District Judges presiding over Special Courts and  
Tribunals having independent administrative  
responsibilities: Rs.3500/- per month; and
  - (d) Senior Civil Judges and Civil Judges:  
Rs.2000/- per month.
2. The Special Pay shall be available w.e.f. 01.01.2019.

**16. Sumptuary Allowance:-**

In partial modification of order No. F.26(12) Nyay/2009 part, dated 03.05.2010 issued by this Department, the following order is made:-

1. The sumptuary allowance to the Judicial Officers shall be revised as under w.e.f. 01.01 2016 :-

District Judges	Rs. 7,800/- per month
Senior Civil Judges	Rs. 5,800/- per month
Civil Judges	Rs. 3,800/- per month
2. The following categories of Judicial Officers shall get Rs.1,000/- (One thousand) per month more by virtue of their status or the additional responsibilities they shoulder:-
  - Principal District Judge in-charge of administration in the Districts/Cities.
  - District Judges in Selection Grade and Super Time-scale.
  - Director of Judicial Academy/Judicial Training Institute/Member Secretary, State Legal Services Authority.
  - Chief Judicial Magistrate/Chief Metropolitan Magistrate.
3. No sumptuary allowance shall be payable to retired Judicial Officers.



### 17. Transfer Grant:-

In continuation and partial modification of order No. F.11(3) Nyay/2002, dated 05.07.2006 issued by this Department, the following order is made:-

1. On transfer, the composite transfer grant shall be equivalent to one month's basic pay.
2. If the transfer is to a place at a distance of 20 kilometers or less or within the same city (if it involves actual change of residence), the transfer grant shall be 1/3rd of the basic pay.
3. For the transportation of personal effects, the O.M. dated 13.07.2017 (annexed as Appendix I) issued by the Department of Expenditure, Government of India pursuant to the recommendations of VII CPC shall apply.
4. In case of transportation by road, the admissible amount shall be Rs.50/- per km. inclusive of labour charges for loading and unloading or the actual whichever is lower. The said amount shall be raised by 25% when the DA increases by 50%.
5. The recommendations will come into effect from 01.01.2016.
6. The Officers who have undergone transfer(s) after 01.01.2016 and their claims for transfer grant paid as per pre-revised pay scales, shall be paid the differential amount on the basis of revised pay w.e.f. 01.01.2016.

The amount already drawn as per existing provisions shall be reduced from the revised amount.

This order is being issued in accordance with the concurrence of the Finance Department vide I.D. No. 192400029 Dated 22.02.2024.


By Order of the Governor

  
(Gyan Prakash Gupta)

Principal Secretary

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
- 2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
- 3 निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 5 महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
- 8 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
- 9 वित्त (नियम/बजट/व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 11 रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 12 समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
- 13 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के दिशेषांक में प्रकाशनार्थ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. समस्त जिला कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 17 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
- 18 रक्षित पत्रावली।

 3.24  
(अंशुतोष कुमावत)

संयुक्त शासन सचिव